

India : Democracy and Development

भारत : लोकतंत्र और विकास

Important Questions with Answers

REVISION CLASS 01

Examine the role of democracy in India.

भारत में लोकतंत्र की भूमिका का परीक्षण कीजिए।

1. Participation of the People:

- In India, democracy guarantees active citizen participation in governance. Citizens can elect their representatives through regular elections for the central and state governments. This empowers people, as they can choose leaders who best represent their interests. The process is transparent and encourages political awareness among the masses.
- **भारत में लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी:**
भारत में लोकतंत्र नागरिकों को शासन में सक्रिय रूप से भाग लेने की गारंटी देता है। नागरिक अपनी पसंद के प्रतिनिधियों को चुनने के लिए नियमित चुनावों में भाग लेते हैं। इससे लोगों को सशक्तिकरण मिलता है, क्योंकि वे उन नेताओं को चुन सकते हैं जो उनके हितों का सही तरीके से प्रतिनिधित्व करते हैं। यह प्रक्रिया पारदर्शी है और आम जनता में राजनीतिक जागरूकता को बढ़ावा देती है।

2. Universal Franchise:

- A key feature of India's democracy is that it allows all adult citizens, regardless of their socioeconomic background, caste, religion, or gender, to vote. This ensures that every citizen has an equal say in shaping the nation's policies. This is an important step towards achieving equality and social justice.
- **सार्वभौमिक मताधिकार:**
भारत के लोकतंत्र का एक प्रमुख पहलू यह है कि यह सभी वयस्क नागरिकों को, चाहे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति, जाति, धर्म या लिंग कुछ भी हो, मतदान का अधिकार देता है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक नागरिक का राष्ट्रीय नीतियों को आकार देने में समान अधिकार हो। यह समानता और सामाजिक न्याय की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है।

3. Protection of Fundamental Rights:

- The Indian Constitution guarantees fundamental rights to all citizens, which include freedom of speech, right to equality, and right to life. These rights protect individuals from exploitation and ensure their personal and social

freedom. Courts can intervene if these rights are violated, and remedies can be sought through legal means.

○ **मौलिक अधिकारों की सुरक्षा:**

भारतीय संविधान सभी नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता का अधिकार और जीवन का अधिकार शामिल हैं। ये अधिकार व्यक्तियों को शोषण से बचाते हैं और उनकी व्यक्तिगत और सामाजिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। यदि ये अधिकार उल्लंघित होते हैं, तो न्यायालय हस्तक्षेप कर सकते हैं और कानूनी उपायों से समाधान प्राप्त किया जा सकता है।

4. **Decentralization of Power:**

○ India follows a decentralized democratic system where power is distributed between the central government, state governments, and local bodies. This allows for better governance, as decisions can be made at levels closer to the people. Local governance (such as Panchayats and Municipalities) ensures that even remote regions have a voice.

○ **शक्ति का विकेंद्रीकरण:**

भारत विकेंद्रीकृत लोकतांत्रिक प्रणाली का पालन करता है, जहां शक्ति केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के बीच वितरित होती है। यह बेहतर शासन सुनिश्चित करता है, क्योंकि निर्णय उन स्तरों पर लिए जा सकते हैं जो लोगों के करीब होते हैं। स्थानीय शासन (जैसे पंचायतें और नगरपालिका) यह सुनिश्चित करता है कि दूरदराज के क्षेत्रों की भी आवाज़ सुनी जाए।

5. **Political Pluralism:**

○ India's democracy supports a multi-party system, where different political ideologies can coexist and compete for power. This diversity allows for a healthy debate on various issues such as social justice, development, and foreign policy, enabling the population to choose from a range of perspectives.

○ **राजनीतिक बहुलतावाद:**

भारत का लोकतंत्र एक बहुदलीय प्रणाली का समर्थन करता है, जहाँ विभिन्न राजनीतिक विचारधाराएँ सह-अस्तित्व में रहती हैं और सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं। यह विविधता विभिन्न मुद्दों पर स्वस्थ बहस को बढ़ावा देती है, जैसे सामाजिक न्याय, विकास और विदेश नीति, जिससे जनसंख्या को विभिन्न दृष्टिकोणों में से चुनने का अवसर मिलता है।

6. **Challenges:**

○ Despite its successes, India faces challenges such as corruption, caste-based discrimination, poverty, and illiteracy. These issues undermine the true essence of democracy, as they hinder the equitable distribution of resources and opportunities. There are also concerns about voter manipulation and the misuse of money power in elections.

○ **चुनौतियाँ:**

अपनी सफलताओं के बावजूद, भारत भ्रष्टाचार, जाति आधारित भेदभाव, गरीबी और अशिक्षा जैसी समस्याओं का सामना करता है। ये मुद्दे लोकतंत्र के असली सार को कमजोर करते हैं क्योंकि ये संसाधनों और अवसरों का समान वितरण बाधित करते हैं। इसके अतिरिक्त, चुनावों में मतदाताओं के साथ छल और धन के दुरुपयोग को लेकर भी चिंताएँ हैं।

Write short note on Judicial Review.

न्यायिक समीक्षा पर एक टिप्पणी लिखिए।

1. Definition:

- Judicial review is the power of the judiciary to examine the constitutionality of laws and governmental actions. It ensures that laws passed by the legislature and actions by the executive are within the framework of the Constitution. The courts can strike down laws that violate the Constitution.

○ परिभाषा:

न्यायिक समीक्षा न्यायपालिका का वह अधिकार है जिसके द्वारा वह कानूनों और सरकारी कार्रवाइयों की संविधानिकता का परीक्षण करती है। यह सुनिश्चित करता है कि विधायिका द्वारा पारित कानून और कार्यपालिका द्वारा की गई कार्रवाइयाँ संविधान के ढाँचे के भीतर हों। न्यायालय उन कानूनों को रद्द कर सकते हैं जो संविधान का उल्लंघन करते हैं।

2. Role of the Judiciary:

- The judiciary acts as a safeguard against unconstitutional laws and arbitrary government actions. It ensures that all government actions, whether by the legislature, executive, or any other body, comply with the Constitution and fundamental rights.

○ न्यायपालिका की भूमिका:

न्यायपालिका असंवैधानिक कानूनों और मनमानी सरकारी कार्रवाइयों के खिलाफ सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती है। यह सुनिश्चित करती है कि सरकार के सभी कार्य, चाहे वह विधायिका, कार्यपालिका, या कोई अन्य संस्था द्वारा किए जाएं, संविधान और मौलिक अधिकारों के अनुरूप हों।

3. Supreme Court's Power:

- The Supreme Court of India has the final say on interpreting the Constitution. It can invalidate laws passed by Parliament or state legislatures if they are found to be unconstitutional. The Court's role is crucial in maintaining the balance between the different branches of government.

○ सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति:

भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या करने में अंतिम निर्णय रखता है। यदि संसद या राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित कोई कानून असंवैधानिक पाया जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय उसे अमान्य कर सकता है। न्यायालय की भूमिका सरकारी शाखाओं के बीच संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण है।

4. Protection of Fundamental Rights:

- Judicial review serves as a check on the violation of fundamental rights by the state or other powerful entities. If any law or policy violates the fundamental rights of citizens, the judiciary has the power to declare it void.

○ मौलिक अधिकारों की रक्षा:

न्यायिक समीक्षा राज्य या अन्य शक्तिशाली संस्थाओं द्वारा मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर नियंत्रण का कार्य करती है। यदि कोई कानून या नीति नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो न्यायपालिका इसे अमान्य घोषित करने का अधिकार रखती है।

5. Kesavananda Bharati Case:

- In the landmark Kesavananda Bharati case (1973), the Supreme Court established that Parliament can amend the Constitution but cannot alter its

"basic structure." This ruling expanded the scope of judicial review and safeguarded the integrity of the Constitution.

○ **केसवकत्रा भारती मामला:**

ऐतिहासिक केसवकत्रा भारती मामले (1973) में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्थापित किया कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसकी "मूल संरचना" को परिवर्तित नहीं कर सकती। इस फैसले ने न्यायिक समीक्षा के दायरे का विस्तार किया और संविधान की अखंडता की रक्षा की।

Discuss the nature of caste -inequalities in India.

भारत में जाति आधारित असमानताओं के प्रकृति पर चर्चा कीजिए।

1. Historical Roots:

○ The caste system has ancient roots in India and was originally a social and occupational classification based on hereditary factors. Over time, it became rigid and discriminatory, with certain castes being considered "superior" and others "inferior." This stratification led to severe social and economic inequalities.

○ **ऐतिहासिक जड़ें:**

जाति व्यवस्था भारत में प्राचीन जड़ों से उत्पन्न हुई थी और मूल रूप से यह सामाजिक और व्यवसायिक वर्गीकरण था जो वंशानुगत आधार पर था। समय के साथ यह कठोर और भेदभावपूर्ण बन गई, जिसमें कुछ जातियाँ "श्रेष्ठ" मानी जाती थीं और अन्य "निम्न" मानी जाती थीं। इस विभाजन के कारण गंभीर सामाजिक और आर्थिक असमानताएँ उत्पन्न हुईं।

2. Discrimination and Exclusion:

○ Historically, lower-caste groups, particularly Dalits, faced untouchability, exclusion from education, social participation, and access to resources. These communities were also subjected to violence and humiliation by higher castes.

○ **भेदभाव और बहिष्करण:**

ऐतिहासिक रूप से, निचली जातियों, विशेष रूप से दलितों, को अछूतता, शिक्षा, सामाजिक भागीदारी और संसाधनों से बहिष्कृत किया गया था। इन समुदायों को उच्च जातियों द्वारा हिंसा और अपमान का भी सामना करना पड़ा।

3. Untouchability:

○ The practice of untouchability was legally abolished in India by the Constitution, but it still exists informally in some regions, especially in rural areas. Dalits were historically forced to live in separate colonies and were restricted from entering temples, schools, and using public facilities.

○ **अछूतता:**

अछूतता की प्रथा को भारतीय संविधान द्वारा कानूनी रूप से समाप्त कर दिया गया था, लेकिन यह कुछ क्षेत्रों में अनौपचारिक रूप से अभी भी मौजूद है, विशेषकर ग्रामीण इलाकों में। दलितों को ऐतिहासिक रूप से अलग कॉलोनियों में रहने के लिए मजबूर किया गया था और उन्हें मंदिरों, स्कूलों और सार्वजनिक सुविधाओं में प्रवेश से वंचित किया गया था।

4. Legal Protections and Reservations:

○ The Indian Constitution prohibits caste-based discrimination and provides legal measures to protect the rights of lower castes. It also introduced

affirmative action in the form of reservations (quotas) in education, jobs, and politics for Scheduled Castes (SC), Scheduled Tribes (ST), and Other Backward Classes (OBC).

○ **कानूनी संरक्षण और आरक्षण:**

भारतीय संविधान जाति आधारित भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है और निचली जातियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए कानूनी उपाय प्रदान करता है। इसने अनुसूचित जातियों (SC), अनुसूचित जनजातियों (ST), और अन्य पिछड़ी जातियों (OBC) के लिए शिक्षा, नौकरियों और राजनीति में सकारात्मक कार्रवाई के रूप में आरक्षण (कोटा) की व्यवस्था की।

5. **Persistent Discrimination:**

○ Despite constitutional safeguards, caste-based discrimination continues in many parts of India. Practices like exclusion from social events, caste-based violence, and discrimination in employment and education persist, particularly in rural areas.

○ **सतत भेदभाव:**

संवैधानिक सुरक्षा के बावजूद, भारत के कई हिस्सों में जाति आधारित भेदभाव जारी है। सामाजिक आयोजनों से बहिष्करण, जाति आधारित हिंसा और रोजगार और शिक्षा में भेदभाव जैसी प्रथाएँ बनी रहती हैं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में।

Write short note on Federal System in India.

भारत में संघवाद पर टिप्पणी कीजिए।

1. **Federal Structure:**

○ India follows a federal system where power is shared between the central and state governments. However, it is a unique form of federalism, as the central government has more authority in key areas like defense, foreign affairs, and finance.

○ **संघीय संरचना:**

भारत संघीय प्रणाली का पालन करता है, जहां शक्ति केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच साझा की जाती है। हालांकि, यह संघवाद का एक अद्वितीय रूप है, क्योंकि केंद्रीय सरकार के पास रक्षा, विदेश नीति और वित्त जैसे प्रमुख क्षेत्रों में अधिक अधिकार होता है।

2. **Division of Powers:**

○ The Constitution divides the powers between the Union (central) government and state governments into three lists: the Union List (subjects on which only the central government can legislate), the State List (subjects on which only the state governments can legislate), and the Concurrent List (subjects on which both central and state governments can legislate).

○ **शक्तियों का विभाजन:**

संविधान में शक्ति का विभाजन केंद्रीय (संघ) सरकार और राज्य सरकारों के बीच तीन सूचियों में किया गया है: संघ सूची (वे विषय जिन पर केवल केंद्रीय सरकार कानून बना सकती है), राज्य सूची (वे विषय जिन पर केवल राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं), और समवर्ती सूची (वे विषय जिन पर केंद्रीय और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं)।

3. **Union List:**

- The Union List includes subjects such as defense, foreign affairs, banking, and communications, where only the central government has the authority to make laws. This ensures uniformity in national governance and foreign relations.
 - **संघ सूची:**
संघ सूची में वे विषय आते हैं जैसे रक्षा, विदेश नीति, बैंकिंग, और संचार, जिन पर केवल केंद्रीय सरकार को कानून बनाने का अधिकार होता है। यह राष्ट्रीय शासन और विदेश संबंधों में एकरूपता सुनिश्चित करता है।
4. **State List:**
- The State List includes subjects such as police, public health, agriculture, and local government, which are primarily managed by state governments. This enables states to legislate according to local needs and conditions.
 - **राज्य सूची:**
राज्य सूची में वे विषय शामिल हैं जैसे पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, और स्थानीय शासन, जो मुख्य रूप से राज्यों सरकारों द्वारा संचालित होते हैं। यह राज्यों को स्थानीय आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार कानून बनाने की अनुमति देता है।
5. **Concurrent List:**
- The Concurrent List includes areas like education, criminal law, and marriage, where both the central and state governments can make laws. In case of a conflict, central laws prevail.
 - **समवर्ती सूची:**
समवर्ती सूची में ऐसे क्षेत्र शामिल हैं जैसे शिक्षा, आपराधिक कानून, और विवाह, जिन पर केंद्रीय और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। यदि कोई संघर्ष होता है, तो केंद्रीय कानून लागू होता है।
6. **Asymmetry of Power:**
- The central government holds more significant powers, especially in matters of national importance. In situations where states fail to act on certain issues, the central government can step in and take necessary actions.
 - **शक्ति का विषमतापूर्ण वितरण:**
केंद्रीय सरकार के पास अधिक महत्वपूर्ण शक्तियाँ होती हैं, विशेष रूप से राष्ट्रीय महत्व के मामलों में। उन परिस्थितियों में जहाँ राज्य कुछ मुद्दों पर कार्रवाई करने में असफल रहते हैं, केंद्रीय सरकार हस्तक्षेप कर सकती है और आवश्यक कदम उठा सकती है।
7. **Role of Supreme Court:**
- The Supreme Court of India plays a crucial role in resolving disputes between the central and state governments. It has the authority to interpret the Constitution and settle any conflicts regarding the distribution of powers.
 - **सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका:**
भारत का सर्वोच्च न्यायालय केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच विवादों का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके पास संविधान की व्याख्या करने और शक्तियों के वितरण को लेकर किसी भी संघर्ष को निपटाने का अधिकार है।